मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

मज़दूरों ने शारीरिक चुनौतियों को भी ललकारा है 2
प्रदेश में घोटालों से घिरी है सरकार 4
मज़दूर लेबर कोड्स का विरोध क्यों कर रहे हैं? 5
पाखंडियों से सवाल करो; ज्ञान-विज्ञान से नाता जोड़ो 6
'ग्रेप' की नौटंकी से बढ़ता जा रहा है वायु प्रदूषण 8

वर्ष 36 | अंक 50 | फरीदाबाद | 23-29 अक्टूबर 2022 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

हिमाचल चुनाव के लिये भाजपा ने बलात्कारी हत्यारे बाबा को बनाया पिताजी

गुरमीत राम रहीम को 40 दिन के लिये जेल से निकाला

फ़रीदाबाद (म.मो.) हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की भाजपाई सरकार होने के बावजूद वहां कोई भी ऐसा काम सरकार नहीं कर सकी जिसके बूते, अगले माह होने वाले चुनावों में भाजपा वोट मांग सके। दरअसल देश की उन्नति के लिये काम करना तो भाजपा के एजेंडा में कभी रहा ही नहीं। इनका भी लक्ष्य लूट कमाई के लिये सत्ता में बने रहने का ही रहा है। इसके लिये जनता में जाति व धर्म के नाम पर फूट डालने तथा उन्हें आपस में लड़ाये रखना भाजपा को अधिक रास आता है।

इसके साथ-साथ जनता में अंधविश्वास फैला कर व धर्म की अफ़ीम चटा कर नशे में रखना जरूरी है। इस

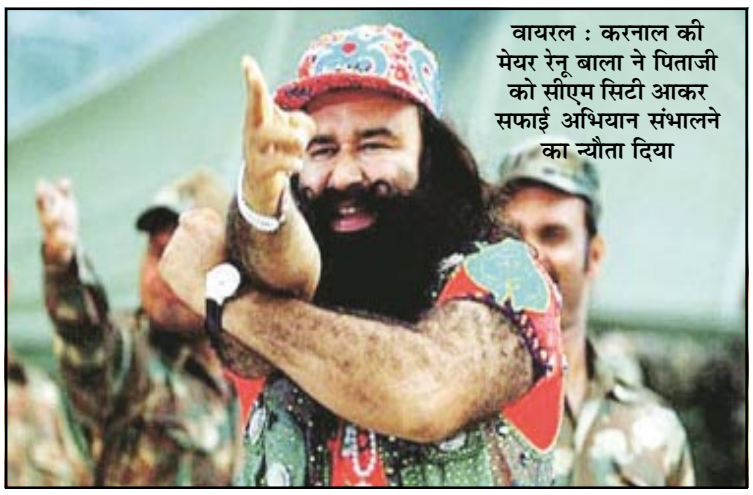

वायरल : करनाल की मेयर रेनू बाला ने पिताजी को सीएम सिटी आकर सफाई अभियान संभालने का न्यौता दिया

काम के लिये देश में तरह-तरह के पाखंडी एवं अपराधी बाबों को धर्मगुरू के रूप में स्थापित करना भाजपा को कहीं ज्यादा रास आता है। वैसे तो धर्म की अफीम व बाबों का सहारा लगभग तमाम पूंजीवादी पार्टियां लेती हैं परन्तु इस मामले में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं।

हिमाचल में चुनाव की घोषणा होने से पूर्व ही भाजपा ने बलात्कारों एवं हत्या में सजायाफ्ता बाबा गुरमीत राम को रोहतक जेल से 40 दिन के लिये निकालने की समय पूर्व योजना बना ली थी। उसी योजना के तहत हरियाणा की खट्टर सरकार ने बीते सप्ताह उसे 40 दिन की पैरोल पर जेल से निकाल दिया। इससे पहले पंजाब चुनाव के समय भी इस पाखंडी अपराधी को इसी तरह जेल से निकाला गया था। परन्तु पंजाब की जनता ने न केवल अकालियों, भाजपाईयों व कांग्रेसियों को बुरी तरह से हरा कर स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे लोग ऐसे किसी पाखंडी के बंधुआ वोटर नहीं हैं।

सुधी पाठक भूले नहीं होंगे कि किस प्रकार इस बाबे ने धर्म की अफ़ीम चटा कर अपनी ऊन दो शिष्याओं का बलात्कार किया था जो अपने मां-बाप की मूर्खता के चलते इसके शिकंजे में फंस गई थी। डेरा स्थल सिरसा के पत्रकार रामचन्द्र छत्रपति ने जब इस कांड को प्रकाशित

शेष पेज चार पर

शहंशाह खट्टर ने लगाया राजदरबार, जनता की शिकायतें सुनने की नौटंकी

फ़रीदाबाद (म.मो.) जिस मुख्यमंत्री को अपनी जनता की शिकायतें व समस्यायें अपने दफ्तर में बैठ कर नजर न आती हों तो उसे गली-गली व घर-घर भटकने के बावजूद भी कुछ नजर आने वाला नहीं है। सीट पर बैठे-बैठे ही राज्य के चप्पे-चप्पे की जानकारी प्राप्त करने के लिये मुख्यमंत्री के पास काफी लम्बा-चौड़ा प्रशासनिक अमला होता है। लेकिन यह अमला उतना ही और वैसा ही काम करता है जितना और जैसा कि मुख्यमंत्री चाहे।

सरकारी अमले के अलावा मीडिया भी सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने का सरल एवं सटीक स्रोत है। लेकिन यहां जानकारियां लेना कौन चाहता है और क्यों चाहेगा, क्योंकि उसे तो करना कुछ है नहीं? हां, कुछ न करने के साथ-साथ, जनता को बेवकूफ बनाने के लिये कुछ करते हुए दिखना बहुत जरूरी है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिये खट्टर महोदय ने यहां पर दिनांक 16 अक्टूबर रविवार के दिन दरबार लगा कर जनता की शिकायतें सुनने का नाटक किया।

इससे एक दिन पूर्व भी ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक लेकर जनता की समस्याओं का समाधान करने का नाटक किया था। यह नाटकबाजी खट्टर सरकार की पूर्ववर्ती सरकारें भी लगभग इसी तरह परम्परागत ढंग से करती रही थीं। इस मीटिंग से संतुष्टि न पाकर खट्टर ने अगले ही दिन के लिये दरबार का आयोजन कराया। इसके लिये प्रशासन ने कुछ दिन पूर्व ही जनता से शिकायतें लेनी शुरू कर दी थीं। नासमझ जनता को लगने लगा था कि खट्टर साहब उनकी शिकायत सुनेंगे और तुरन्त समाधान करके उसे निहाल कर देंगे।

जानकार बताते हैं कि कुछ शिकायतें लेने के बाद, हजारों में आये शिकायतकर्ताओं को भगा दिया। दरबार में आने के लिये उमड़ी भीड़ को भी पुलिस ने भगा दिया था। करीब तीन घंटे चले इस नाटक में खट्टर ने 15 शिकायतें तो सुनी बाकी शिकायतों का गट्ठर अपने उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के सुपुर्द कर गये जिनकी नालायकी एवं बेइमानी के चलते ये समस्यायें पैदा होती हैं। यदि ये अधिकारी समाधान करने लायक होते तो ये समस्यायें पैदा ही न होती।

पत्रकारों के कैमरे से डरते खट्टर

खट्टर के शाही दरबार में पत्रकार व छायाकार भी अच्छी-खासी संख्या में मौजूद थे। एक फरियादी द्वारा फरीयाद करने तथा खट्टर द्वारा जवाब देने के दृष्य की जब एक पत्रकार वीडियो बनाने लगा तो उसे खट्टर के इशारे पर अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया। उसके बाद एक अधिकारी द्वारा घोषणा की गई कि केवल सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकार ही यहां ठहरें, बाकी सब बाहर हो जायें। इस पर वहां मौजूद कुछेक को छोड़कर तमाम तरह के पत्रकार दुबक कर बैठ गये।

विदित है कि शहर भर में बमुश्किल 25-30 पत्रकार ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। किसे मान्यता देनी है और किसे नहीं यह पूर्णतया सरकार की मनमर्जी पर निर्भर करता है। जाहिर है ऐसे में सरकार उन्हीं पर अपनी मान्यता बरसायेगी जिनके लेखन एवं रिपोर्टिंग से सरकार प्रसन्न होती होगी। संदर्भवश 36 वर्ष पूराना **'मज़दूर मोर्चा'** भी गैरमान्यता प्राप्त पत्र है।

न केवल खट्टर दरबार में बल्कि आजकल अधिकांश अधिकारी भी मोबाइल कैमरों से बचते हैं। अपने कार्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मोबाइल बाहर ही रखवा देते हैं। क्यों?

क्योंकि वे डरते हैं कि उनकी कोई जन एवं कानून विरोधी बात टेप न कर ली जाय। संदर्भवश, अधिकारियों द्वारा की जाने वाली इस कार्रवाई को पंजाब सरकार ने गैरकानूनी घोषित कर दिया है। वहां कोई भी अधिकारी किसी को भी मोबाइल बाहर छोड़ने के लिये नहीं कह सकता।